



भारत-किर्गिस्तान: पारस्परिक प्रगति हेतु बढ़ता सहयोग

डॉ. अतहर ज़फ़र*

कार्यकारी सारांश

भारत और किर्गिस्तान के बीच सौहार्दपूर्ण/आत्मीय संबंध हैं। किरगिज़ गणराज्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के दावे और कश्मीर पर नई दिल्ली के रुख का समर्थन करता है।

किर्गिस्तान में मध्य एशिया में ज्ञान और मनोरंजन के केन्द्र के रूप में उभरने की क्षमता है। यह देश बड़ी संख्या में छात्रों, पर्यटकों और स्वास्थ्य लाभार्थियों को आकर्षित करता है।

किरगिज़ किसान आम तौर पर रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं करते हैं, इस प्रकार, वहाँ जैविक खेती की संभावनाएं मौजूद हैं। भारतीय राज्य जम्मू व कश्मीर और किरगिज़ गणराज्य के कुछ क्षेत्रों के बीच स्थलाकृतिक समानताओं को देखते हुए संयुक्त कृषि की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। अत्यधिक मांग वाले उत्पाद केसर के उत्पादन की संभावना का पता लगाया जा सकता है।

भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं को किर्गिस्तान का नियमित दौरा करने की आवश्यकता है।

प्रस्तावना

1990 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (यूएसएसआर) से स्वतंत्र होकर किरगिज़ गणराज्य का अभ्युदय किरगिज़ लोगों के लिए एक यादगार घटना रही है जो अपने तकदीर का निर्धारण अब स्वयं ही करने में समर्थ हैं। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, इस देश ने आर्थिक सुधारों से ज्यादा राजनीतिक सुधारों को तरजीह दी, जबकि कजाकिस्तान जैसे अन्य गणराज्यों ने दूसरा विकल्प चुना। किर्गिस्तान इस क्षेत्र में एकमात्र देश है जहाँ लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली है और इसलिए इसे अक्सर 'लोकतांत्रिक द्वीप' कहा जाता है। तथापि, 2005 और 2010 में हुई दो क्रमिक क्रांतियों के कारण इसकी आर्थिक प्रगति अवस्त्रुद्ध हुई और इसने यहां के सामाजिक ताने-बाने को बिगाड़ दिया, जिसके परिणामस्वरूप, देश में विशेष रूप से दक्षिण में कई अप्रिय घटनाएं, विस्थापन और मौतें हुईं।

किर्गिस्तान की अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत बहुत छोटी करीब 7 अरब अमरीकी डॉलर की है, लेकिन इस देश में प्राकृतिक संसाधन भरे पड़े हैं। यह मध्य एशिया में उज़बेकिस्तान के बाद सोने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और इसकी जलविद्युत क्षमता 150 अरब किलोवाट से अधिक है, जो इस क्षेत्र में ताजिकिस्तान के बाद सबसे अधिक है। किर्गिस्तान राष्ट्रीय मुद्रा लागू करने वाला, भूमि के निजीकरण की शुरुआत करनेवाला और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का सदस्य बननेवाला मध्य एशिया का पहला देश है। तथापि, निवेशों और निधियों की कमी, प्राकृतिक संसाधनों का कम उपयोग और उन्नत प्रौद्योगिकियों की कम उपलब्धता, इसके तेज आर्थिक विकास को बाधित करते हैं। बिश्केक व्यापार अनुकूल वातावरण तैयार करने का प्रयास करता रहा है और यह (अपने) देश में विदेशी निवेश को आमंत्रित कर रहा है। साथ ही, यह पड़ोसी देशों से भागीदारी बढ़ाने का भी प्रयास कर रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी और उभरती अर्थव्यवस्था है और दोनों देश अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकते हैं तथा संपूरक/प्रतिपूरक वस्तुओं का विकास कर सकते हैं। इस नीति सार में आपसी हित के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया है, जो द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा दे सकते हैं और पारस्परिक लाभों को अधिकतम कर सकते हैं।

किरगिज़ गणराज्य के साथ भारत का संपर्क

भारत किर्गिस्तान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में शामिल है और दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण राजनैतिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। किर्गिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की पूर्ण सदस्यता के भारत के दावे का समर्थन करता है। बिश्केक इस्लामिक सम्मेलन संगठन (ओआईसी) सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में कश्मीर मुद्दे

पर नई दिल्ली का समर्थन भी करता है और इसे भारत और पाकिस्तान के बीच आपस में सुलझाया जाने वाला द्विपक्षीय मुद्दा मानता है। मध्य एशिया में अपने विस्तारित पड़ोसियों के साथ भारत के संबंधों में किर्गिस्तान की केन्द्रीय भूमिका और महत्व को रेखांकित करते हुए, नई दिल्ली ने जून 2012 में प्रथम मध्य एशिया-भारत वार्ता के दौरान बिश्केक में अपनी 'मध्य एशिया संपर्क' नीति की शुरुआत की।

तथापि, सौहार्दपूर्ण संबंधों के बावजूद, भारत-किर्गिस्तान आर्थिक संबंध अपनी क्षमता से काफी कम प्रतीत होते हैं। अन्य क्षेत्रीय देशों के साथ मध्य एशिया के व्यापार की तुलना में (भारत-किर्गिस्तान) व्यापार सीधा सड़क-मार्ग संपर्क का अभाव और घुमावदार रास्तों के चलते ज्यादा समय लगने के साथ-साथ लागत बढ़ने के कारण प्रभावित होता है। वर्ष 2013-14 में कुल द्विपक्षीय व्यापार 3 करोड़ 50 लाख अमरीकी डॉलर था और यह किर्गिस्तान को 3 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक के निर्यात और 10 लाख अमरीकी डॉलर से भी कम के आयात के साथ भारत के पक्ष में था। इसे वहनीय बनाने के लिए इसमें संशोधन करने की जरूरत है। भारत कृषि उत्पादों, खनिज संसाधनों जैसेकि कोयला, दुर्लभ मिट्टी/खनिज और स्वर्ण आदि के निर्यात की संभावनाएं तलाश रहा है। किर्गिस्तान भारत की बढ़ती खाद्य सुरक्षा और खनिज संसाधन संबंधी आवश्यकताओं को सम्पूरित कर सकता है।

भारत-किर्गिस्तान व्यापार

करोड़ अमरीकी डॉलर में मूल्य

क्र.सं.	वर्ष	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014
1.	निर्यात	26.84	25.79	30.55	34.99	34.54
2.	आयात	0.64	1.20	0.89	2.09	0.64
3.	कुल व्यापार	27.48	26.98	31.44	37.07	35.18
4.	प्रतिशत वृद्धि	लागू नहीं	-1.79	16.50	17.92	-5.10
5.	व्यापार संतुलन	26.20	24.59	29.66	32.90	33.90

स्रोत: वाणिज्य विभाग

भारत का बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण तथा मध्यम-अवधि की संस्तुतियां

इस क्षेत्र के साथ आर्थिक एकीकरण के अपने प्रयासों में, किर्गिस्तान इस वर्ष यूरेशियाई आर्थिक संघ (ईईयू), जिसका उद्घाटन 1 जनवरी, 2015 को हुआ, में शामिल होने की तैयारी कर चुका है। भारतीय व्यापार घरानों को यूरेशियाई आर्थिक संघ (ईईयू) आर्थिक क्षेत्र के खुलने के कारण उत्पन्न होने वाली

मांगों को पूरा करने के लिए किरगिज़ भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने की आवश्यकता है। भारत सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और औषध क्षेत्र में अग्रणी बना हुआ है और इन क्षेत्रों में संभावनाएं तलाश सकता है। इसके अलावा, किर्गिस्तान मध्य एशिया और यूरोप में व्यापार के लिए एक प्रमुख पारगमन मार्ग के रूप में उभर रहा है।

भारत में आर्थिक आवश्यकताओं, किर्गिस्तान में अवसर और संसाधनों की उपलब्धता, जो 'मध्य एशिया संपर्क' नीति में वर्णित घटकों के समकालिक हैं, का ध्यान रखते हुए नई दिल्ली दोनों मित्र देशों के बीच आर्थिक संबंधों को घनिष्ठ बनाने के लिए एक बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण तैयार कर सकता है।

स्वर्ण, जवाहरात तथा आभूषण: किर्गिस्तान एक महत्वपूर्ण सोना उत्पादक देश है, जिसका वार्षिक उत्पादन लगभग 20 टन है। यह विशाल भारतीय आभूषण तथा गहना विनिर्माण और उपभोग केन्द्रों तथा विकसित यूरोपीय बाजारों के निकट अवस्थित है। पड़ोसी देश ताजिकिस्तान के पास मूल्यवान और अर्ध-कीमती पत्थरों का भंडार है। भारत किर्गिस्तान में आभूषण निर्माण की संभावनाएं तलाश सकता है जिससे ये उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनेंगे और किर्गिस्तान के लिए रोजगार तथा राजस्व बढ़ेंगे। वर्तमान में, सोने का निर्यात कुल किरगिज़ निर्यात का लगभग 34 प्रतिशत है, सोने के विनिर्मित गहनों/आभूषणों से राजस्व में वृद्धि होगी।

पर्यटन: किर्गिस्तान में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास तेजी से हो रहा है। इस देश में अनेक प्राकृतिक पर्यटन स्थल हैं, जैसेकि विश्व प्रसिद्ध झील इसिक कुल। सरकार द्वारा आर्थिक विकास में पर्यटन को प्राथमिकता दी गई है और भारतीय आतिथ्य क्षेत्र इस देश में पर्यटन की बुनियादी सुविधा विकसित करने में निवेश कर सकता है। यह आश्चर्य की बात है कि वर्ष 2013 में 55 लाख आबादी वाले इस छोटे से देश ने 30 लाख से भी अधिक पर्यटक आकर्षित किए। भारतीय दूर ऑपरेटर और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता इसिक कुल (झील) के आसपास प्राचीन प्राकृतिक पर्यावरण में पर्यटन और स्वास्थ्य पुनर्निर्माण की संभावनाओं का पता लगा सकते हैं। बिश्केक नई दिल्ली से लगभग साढ़े तीन घंटे की उड़ान (की दूरी पर) है। वीजा सुविधा से संबंधित द्विपक्षीय नियमों में आगे और विचार-विमर्श करने और सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है। भारत (अपने यहां) हाल ही में शुरू की गई आगमन पर वीजा (वीजा ऑन एराइवल) सुविधा में किर्गिस्तान को शामिल कर सकता है। इसी प्रकार, किर्गिस्तान भारतीयों को आगमन पर वीजा और दीर्घकालिक बहुप्रवेश वीजा दे सकता है।

कृषि: कृषि मुख्यतः दो कारणों से दोनों देशों के बीच सहयोग का एक और आशाजनक क्षेत्र है; पहला, वहाँ भूमि के विशाल भूभाग उपलब्ध हैं और किरगिज़ किसान आम तौर पर रासायनिक उर्वरक का प्रयोग

नहीं करते इसलिए, जैविक खेती और जैविक उत्पादनों की अत्यधिक संभावनाएं मौजूद हैं जिसकी मांग स्वास्थ्य के प्रति सजग पड़ोस के यूरोपीय बाजारों में और भारत में अधिकाधिक बढ़ रही है। दूसरा, किर्गिस्तान और भारत के जम्मू व कश्मीर राज्य की स्थलाकृति में समानता केसर और पुष्प कृषि के संयुक्त उत्पादन की संभावनाओं के द्वार खोलता है, जैसा इस भारतीय राज्य में प्रचलन किया जाता है।

शिक्षा: बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, कम लागत, अपेक्षाकृत खुला लचीला मानदंड आदि किर्गिस्तान को विदेशी छात्रों को बड़ी संख्या में आकर्षित करने में सक्षम बनाता है। छात्र मुख्य रूप से मेडिकल/चिकित्सा शिक्षा के लिए दाखिला लेते हैं; अंग्रेजी में शिक्षण का प्रावधान भी एक प्रोत्साहन है। लगभग 2,000 भारतीय छात्र मुख्यतः चिकित्सा/डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। भारत में जनसंख्या और डॉक्टरों के अनुपात में एक बड़ा अंतर है। भारतीय शैक्षिक संस्थाओं को भारतीय छात्रों को किर्गिस्तान में पढ़ाने के लिए लीज/पट्टे पर वहां के अस्पतालों और छात्रावासों की बुनियादी सुविधा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। औसतन, किर्गिस्तान में चार वर्ष के चिकित्सा पाठ्यक्रम के लिए एक भारतीय छात्र को लगभग 15-16 लाख भारतीय रुपए का खर्च आता है, जो उसी पाठ्यक्रम के लिए भारत में खर्च की गई राशि के बराबर अथवा कई मामलों में उससे भी कम है। तथापि, एक दूसरे की डिग्री को मान्यता देने पर दोनों देशों के बीच बातचीत करने की आवश्यकता है।

मनोरंजन उद्योग: किर्गिस्तान का नैसर्गिक सौंदर्य भारतीय फिल्म उद्योग को, जो इस देश में बहुत प्रचलित है, भारतीय फिल्मों, विज्ञापन और टीवी धारावाहिक का वहनीय मूल्य पर पास के स्थानों में फिल्मांकन करने के लिए अवसर प्रदान करता है। इससे भारत में फिल्म निर्माण की लागत कम करने और इस क्षेत्र में भारतीय दृश्य-श्रव्य बाजार के विस्तार में काफी मदद मिलेगी।

तात्कालिक उपायों लिए संस्तुतियां

किर्गिस्तान भारत का मित्र रहा है इसलिए इस क्षेत्र के साथ भारत के संपर्क और भारत की मध्य एशिया संपर्क नीति में इस देश को प्राथमिकता दी जाती है। इन उपायों पर ज्यादा निवेश किए बिना अमल किया जा सकता है और यह इस क्षेत्र के साथ जुड़ने और दोनों देशों के बीच राजनैतिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

गोलाकार वायु मार्ग: भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच सीधा हवाई संपर्क नहीं है। यात्रियों को भारत से दुबई, इस्तांबुल, काबुल अथवा अल्माटी होकर बिश्केक जाना पड़ता है, जिससे लागत बढ़ जाती है और पारगमन तथा सामान संबंधी मुद्दों पर अतिरिक्त समय भी लगता है, जिसके कारण व्यापारी वर्ग

किर्गिस्तान में संभावनाएं तलाशने में कम उत्साह दिखाते हैं। सामान्यतः भारत और मध्य एशियाई शहरों के बीच हवाई संपर्क एक मुद्दा रहा है। विशेषकर भारत के व्यावसायिक एयरलाइन्स दिल्ली-श्रीनगर-दुशान्बे-अशगाबात-ताशकंद-बिश्केक-आल्माटी-उरुमची-दिल्ली के लिए सप्ताह में एक या दो बार चक्रीय उड़ान परिचालन की संभावनाओं का पता लगा सकते हैं। इससे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शहरों को जोड़ते हुए एक क्षेत्रीय मालाकार वायु मार्ग खुलेगा।

उच्च स्तरीय राजनीतिक यात्रा: चीन और रूस सहित क्षेत्रीय देशों के नेता मध्य एशियाई देशों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क बनाए रखते हैं, जिनमें से कई आजादी के समय से अपने देश पर शासन कर रहे हैं। द्विपक्षीय संबंधों पर जोर देने के लिए उच्च स्तरीय आपसी राजनीतिक दौरे नियमित अंतराल पर किए जाने चाहिए।

भारतीय बैंक शाखाएं खोलना: दोनों देशों के बीच आर्थिक संपर्क और सुचारू वाणिज्यिक लेन-देन के लिए, भारतीय बैंकों को किर्गिस्तान में शाखाएं खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अथवा, उस देश में किसी भारतीय बैंक की शाखा खोले जाने तक, सूचना प्रौद्योगिकी साधन का उपयोग करके, किसी किरगिज़ बैंक को भारतीय इकाई की ओर से नोडल भारतीय बैंक बनाने और किसी भारतीय बैंक को किरगिज़ इकाई की ओर से नोडल किरगिज़ बैंक बनाने की संभावनाएं तलाशी जा सकती है।

सांस्कृतिक, शैक्षिक और लोगों के आपसी संपर्क: सांस्कृतिक रूप से, भारत और किर्गिस्तान में कई समानताएं हैं। किर्गिस्तान में समाज आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता प्रतीत होता है और उस देश से कई छात्र धर्म का अध्ययन करने के लिए विदेश जाते हैं। प्रसिद्ध और व्यापक रूप से सम्मानित भारतीय मदरसों को किर्गिस्तान के छात्रों को दाखिला देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इससे उन्हें अधिक सहिष्णु और समावेशी भारतीय-इस्लामी परंपराओं को जानने का अवसर मिलेगा और एक बहु-धार्मिक और लोकतांत्रिक समाज में शिक्षण का मौका मिलेगा। इसी प्रकार, दोनों देश विशेषकर साझा मध्यकालीन इतिहास पर संयुक्त शैक्षिक अनुसंधान को आगे बढ़ा सकते हैं।

* डॉ. अतहर ज़फ़र विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली में अनुसंधान अध्येता हैं।

¹विदेश व्यापार महानिदेशक, निर्यात आयात डेटा बैंक, <http://commerce.nic.in/eidb/iecnt.asp>, 27 सितंबर, 2014 को एक्सेस किया गया।